



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 1986/माघ 10, 1907

No. 49]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 1986/MAGHA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1986

अधिसूचना

सं. 6/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. सं. 76(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय  
उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की  
गारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय  
उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए  
नमूलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क पहला  
(संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 12 में,  
नियम 210 से पूर्व, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया  
जाएगा, अर्थात् :—

“209. अधिहरण और शास्ति :—(1) इन नियमों के किसी  
अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि  
कोई विनिर्माता, उत्पादक या भाण्डागार का अनुज्ञापिधारक,—

(क) इन नियमों के उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन में  
कोई उत्पाद-शुल्क माल हटाता है ; या

(ख) उसके द्वारा विनिर्मित, उत्पादित या भाण्डारित  
किसी उत्पाद-शुल्क माल का हिसाब नहीं देता  
है ; या

(ग) अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपेक्षित अनुज्ञापि  
के लिए आवेदन किए बिना किसी उत्पाद-शुल्क  
माल के विनिर्माण, उत्पादन या भाण्डारण में  
लगता है ; या

(घ) शुल्क के संदाय का अपवंचन करने की आशय से इन नियमों के सम्बन्ध में से किसी का उल्लंघन करता है, तो, ऐसा समस्त माल अधिहरण का दायी होगा और विनिर्माता, उत्पादक या भाण्डागार का अन्त-जतिधारक उस उत्पाद-शुल्क के, जिसकी दण्डन खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई उल्लंघन किया गया है, मूल्य के तीन गुने से अधिक, या पांच हजार रुपये, जो भी अधिक हो, शास्त्र का दायी होगा।

(2) जहां—

(क) उप-नियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के उल्लंघन की दशा में, उस उप-नियम में निर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क एक लाख रुपये से अधिक है, या

(ख) कोई विनिर्माता, उत्पादक या भाण्डागार का अन्त-जतिधारक, जिसके उत्पाद-शुल्क माल का उप-नियम, (1) के अधीन अधिग्रहण किया गया है और जिस पर उस उप-नियम के अधीन शास्त्र अधिरोपित की गई है, उप-नियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख), या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के उल्लंघन में से किसी का पुनः उल्लंघन करता है और दूसरे या किसी पश्चात्त्वर्ती अवसर के उल्लंघन की दण्डन उत्पाद-शुल्क माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क दस हजार रुपये से अधिक है ;

तो, इस उप-नियम के खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामले में या उक्त उप-नियम के खण्ड (ख) के अधीन आने वाले मामले में (चाहे उस खण्ड के अधीन उल्लंघन दूसरे या किसी पश्चात्त्वर्ती अवसर पर किया गया है) अधिनियम की धारा 33 के अधीन मामले का अभिनिर्धारण करने वाला अधिकारी, उप-नियम (1) के अधीन अधिहरण और शास्त्र के आदेश के अतिरिक्त, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे विनिर्माता, उत्पादक या भाण्डागार के अन्त-जतिधारी के निम्नलिखित में से किसी या सभी के अधिग्रहण का निदेश दे सकेगा, अर्थात् —

- (1) ऐसे माल के विनिर्माण, उत्पादन, भाण्डारण, हटाए जाने या निष्पादन के संबंध में प्रयुक्त कोई भूमि, भवन, संयंत्र, मशीन, सामग्री, वाहन, पशु या कोई अन्य वस्तु ; या
- (2) ऐसी भूमि या ऐसे भवन में या ऐसे संयंत्र, मशीन सामग्री या वस्तु से उत्पादित या विनिर्मित कोई अन्य उत्पाद-शुल्क माल ।” ।

[फा. सं. 208/15/85-के. उ. शृ.-6]

ए. के. प्रसाद, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th January, 1986

### NOTIFICATION

NO. 6186-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 76(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (1st Amendment) Rules, 1986.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Chapter XII of the Central Excise Rules, 1944, before rule 210, the following rule shall be inserted, namely :—

“209. Confiscation and penalty.—(1) Notwithstanding anything contained in any other provisions of these rules, if any manufacturer, producer or licensee of a warehouse,—

- (a) removes any excisable goods in contravention of any of the provisions of these rules; or
- (b) does not account for any excisable goods manufactured, produced or stored by him; or
- (c) engages in the manufacture, production or storage of any excisable goods without having applied for the licence required under section 6 of the Act; or
- (d) contravenes any of the provisions of these rules with intent to evade payment of duty

then, all such goods shall be liable to confiscation and the manufacturer, producer or licensee of the warehouse, as the case may be, shall be liable to a penalty not exceeding three times the value of the excisable goods in respect of which any contravention of the nature referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) has been committed, or five thousand rupees, whichever is greater.

(2) Where—

- (a) in the case of a contravention of the nature referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) the duty leviable on the excisable goods referred to in that sub-rule exceeds one lakh of rupees, or
- (b) any manufacturer, producer or licensee of a warehouse, whose excisable goods were confiscated under sub-rule (1) and upon whom a penalty was imposed under the sub-rule, contravenes again any of the provisions of clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) and the duty leviable on the excisable goods in re-

pect of the contravention for the second or any subsequent occasion exceeds ten thousand rupees,

then, in a case falling under clause (a) of this sub-rule or in a case falling under clause (b) thereof (whether the contravention under that clause has been committed for the second or any subsequent occasion) the officer adjudging the case under section 33 of the Act may, in addition to the award of confiscation and penalty under sub-rule (1), direct, for reasons to be recorded in writing, the confiscation of any or all of the following belonging to such manufacturer, pro-

ducer or licensee of a warehouse, namely :—

- (i) any land, building, plant, machinery, materials, conveyance, animal or any other thing used in connection with the manufacture, production, storage, removal or disposal of such goods; or
- (ii) any other excisable goods on such land or in such building or produced or manufactured with such plant, machinery, materials or things.”.

[F. No. 208/15/85-CX. 6].  
A. K. PRASAD, Under Secy.

